

[2016] 7 एस.सी.आर. 127

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड, एवं अन्य

बनाम

मेसर्स धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड और अन्य

(सिविल अपील क्रमांक 9732/2016)

सितम्बर 27, 2016

[टी.एस.ठाकुर, सी.जे.आई. और ए.एम. खानविलकर, जे.]

अनुबंध - कार्य अनुबंध - सतही खनिकों को तैनात करके कोयला/कोयला माप स्ट्रेटा के निष्कर्षण और हस्तांतरण के लिए - निविदा दस्तावेज के नियमों और शर्तों के साथ-साथ समझौते के अनुसार, समान नियम एवं शर्तों पर निविदा की मात्रा 30% तक घटाई या बढ़ाई जा सकती है - ठेकेदार के अनुरोध पर अनुबंध कार्य पूरा करने का समय बढ़ाया गया था - अनुबंध अवधि के अस्तित्व के दौरान अपीलकर्ता-कंपनी ने 30% अतिरिक्त मात्रा में वृद्धि का आदेश पारित किया - ठेकेदार ने कंपनी से अनुबंध बंद करने का अनुरोध किया और वित्तीय कठिनाई के कारण पूर्ण अनुबंध अवधि के बाद परिचालन से हटने का इरादा बताया - इसलिए कंपनी ने बचा हुआ काम तीसरे पक्ष को ऊंची दर पर दे दिया - कंपनी ने बचा हुआ काम पूरा न करने पर ठेकेदार पर जुर्माना लगाया - जुर्माने में उस कार्य को उच्च दर

पर आवंटित करने के कारण कंपनी को हुई वित्तीय हानि शामिल थी - ठेकेदार ने रिट याचिका दायर की - उच्च न्यायालय ने याचिका स्वीकार की - अपील पर, कहा गया: समझौते के खंड 5 ने कंपनी को अनुबंध के अस्तित्व में रहने के दौरान काम की मात्रा को 30% तक बढ़ाने या घटाने का अधिकार दिया - इसलिए, अनुबंध के संदर्भ में अतिरिक्त काम को अनुबंध अवधि या विस्तारित अवधि के भीतर पूरा करने के लिए ठेकेदार का दायित्व अनिवार्य था। - ठेकेदार ने शेष कार्य पूरा न करके संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन किया - शेष कार्य को उच्च दर पर सौंपने में कंपनी को हुए वित्तीय नुकसान की भरपाई के लिए ठेकेदार उत्तरदायी है - हालाँकि, ठेकेदार को अनुबंध के संदर्भ में दंड माफ करने का अनुरोध करने के लिए कंपनी को अभ्यावेदन देने की स्वतंत्रता दी गई है।

न्यायालय ने अपील को आंशिक रूप से स्वीकार करते हुए माना:

1. अनुबंध के खंड 5 को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। 26 मई 2003 के समझौते का खंड 5 अपीलकर्ताओं को अनुबंध के अस्तित्व में रहते हुए, निविदा की मात्रा को +/- 30% तक कम करने या बढ़ाने का अधिकार देता है। निर्विवाद रूप से, मूल अनुबंध अवधि आईएस•एच अप्रैल, 2004 तक थी। उत्तरदाताओं के कहने पर, इसे 15 जुलाई 2004 तक बढ़ा दिया गया। विस्तारित अनुबंध अवधि यानी 151 जुलाई 2004 की समाप्ति से पहले, 11 जून 2004 को उत्तरदाताओं को अतिरिक्त 30% काम आवंटित

किया गया था। चूंकि अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गई थी और निर्णय को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी, इसने अनिवार्य रूप से उत्तरदाताओं को मूल समझौते के तहत सभी संविदात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य किया, जिसमें काम की निर्धारित मात्रा को पूरा करना भी शामिल था - चाहे वह मूल मात्रा हो या अतिरिक्त मात्रा - 15 जुलाई, 2004 से पहले। यह तथ्य कि कम अनुबंध दर के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, उस अनुबंध संबंधी दायित्व से मुक्त होने के बहाने के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है। [पैरा 18] जे148-एफ-एच; 149-ए.जे

2. कार्य की मूल मात्रा या अतिरिक्त कार्य को निष्पादित करने की संविदात्मक बाध्यता का पालन करने में विफलता, जैसा भी मामला हो, अधूरे काम की सीमा तक अनुबंध के अन्य स्पष्ट खंडों के संदर्भ में अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने के दायित्व के साथ उत्तरदाताओं का दौरा करना चाहिए और विशेष रूप से उसी कार्य को तीसरी एजेंसी के माध्यम से उच्च दर पर निष्पादित कराने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई वित्तीय हानि। तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं ने 15 जुलाई 2004 से पहले 108.47% काम निष्पादित किया, उन्हें अधूरे अनुबंध कार्य (130% में से) के लिए अपीलकर्ताओं को उचित राशि के साथ मुआवजा देने के दायित्व से मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है। [पैरा 19) (149-बी-सी)

3. यह कहना सही नहीं है कि काम की अतिरिक्त मात्रा उन्हें आवंटित नहीं की जा सकती थी, 45 स्पष्ट दिनों के नोटिस पर अनुपस्थित,

वह भी अनुबंध अवधि के अंत में। यह कहना एक बात है कि ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित की जाने वाली अतिरिक्त मात्रा के अनुरूप अतिरिक्त कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हालाँकि, कानून में, यह तर्क देना संभव नहीं है कि भले ही अनुबंध की अवधि अभी भी विद्यमान है, प्रिंसिपल (अपीलकर्ता) अनुबंध अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उस खंड के तहत अनुमत सीमा तक काम की मात्रा बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल (अपीलकर्ताओं) को अनुबंध अवधि को 15 जुलाई, 2004 से आगे बढ़ाने के अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि उत्तरदाताओं को अधूरा अतिरिक्त काम पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। यदि ऐसा अनुरोध उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना था, तो समझौते के खंड 5 के संदर्भ में काम की बढ़ी हुई मात्रा के अनुरूप संपर्क अवधि बढ़ाने के लिए अपीलकर्ताओं पर संबंधित दायित्व होता। इसके बजाय, उत्तरदाताओं ने केवल इस कारण से अनुबंध से बाहर निकलने का विकल्प चुना कि उनके द्वारा सहमत अनुबंध दर बहुत कम थी और इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा था। यह उनके संविदात्मक दायित्व को पूरा न करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है। [पैरा 20] (149-डी-जी)

4. खंड 5 में 45 स्पष्ट दिनों के नोटिस का प्रावधान अपीलकर्ताओं के लिए 30% तक अतिरिक्त मात्रा में काम आवंटित करने में बाधा नहीं था, जबकि अनुबंध की अवधि विद्यमान थी। उक्त शर्त तभी लागू होगी जब

उत्तरदाताओं को मशीन की क्षमता को 30% अतिरिक्त "दैनिक" मात्रा तक बढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को दैनिक मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता के बिना केवल 30% अतिरिक्त मात्रा आवंटित की। अनुबंध अवधि के दौरान अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने और अतिरिक्त "दैनिक" मात्रा बढ़ाने के बीच स्पष्ट अंतर है। [पैरा 21] [149-एच; 150-ए-बी]

5. उत्तरदाताओं का यह तर्क सही नहीं है कि अपीलकर्ता-कंपनी के पास बड़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए समय विस्तार देने का कोई अधिकार नहीं था। यह अन्य संविदात्मक शर्तों जैसे खंड 11.0 से स्पष्ट है - जो निर्धारित मात्रा, सीमा और दर में भिन्नता प्रदान करता है; खंड 13 - अनुबंध पूरा करने का समय और विशेष रूप से खंड 14.0 - पूरा होने की तारीख के विस्तार के लिए। खंड 14.0 (ई) उपलब्ध था और इस स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए था। [पैरा 22] [150-एफ-जी]

6. उत्तरदाताओं ने 130% कार्य (अर्थात् 130 - 108.47%) में से शेष कार्य पूरा न करके, अपने संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन किया। उस हद तक प्रतिवादी अपीलकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हो गए, जिसमें जुर्माना भी शामिल है और विशेष रूप से अधूरे काम को किसी तीसरी एजेंसी (ठेकेदार) को उच्च दर पर सौंपने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई वित्तीय हानि की भरपाई करना शामिल है। [पैरा 23] (151-बी-सी)

7. यह निर्विवाद है कि अधूरे कार्य को किसी तीसरी एजेंसी (ठेकेदार) को अधिक दर पर सौंपने के कारण अपीलकर्ताओं को वित्तीय हानि हुई। यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं को उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ, उत्तरदाताओं को उस दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि जुर्माने के साथ वित्तीय हानि की वसूली के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया गया था। उत्तरदाता अनुबंध के खंड 30.3 के संदर्भ में दंड की अपनी मांग पर पुनर्विचार के लिए अपीलकर्ताओं से संपर्क कर सकते थे; और अपीलकर्ताओं को उनसे वसूल की जाने वाली जुर्माना राशि माफ करने के लिए राजी करें। भले ही यह अपील सफल हो जाए, उत्तरदाताओं को अपीलकर्ताओं - कंपनी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सकता है, जो बदले में कानून के अनुसार इससे निपट सकते हैं। [पैरा 24] (151-एफ-एच;152-ए-सी)

मौला बक्स बनाम भारत संघ (1969) 2 एससीसी 554 : 1970 (1) एससीआर 928; गोरखा सुरक्षा सेवाएँ "सरकार (एनसीटी दिल्ली) और अन्य (2014) 9 एससीसी 105; कुमारी श्रीलेखा विद्यार्थी और अन्य बनाम यूपी राज्य (1991) 1 एससीसी 212: 1990 (1) पूरक एससीआर 625 - संदर्भित।

8. हालाँकि, यह उत्तरदाताओं को अनुबंध की दर के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी से मुक्त नहीं करेगा और अपीलकर्ताओं द्वारा अनुबंध मात्रा के 130% में से अधूरे काम को तीसरी एजेंसी के

माध्यम से उच्च दर पर पूरा करने के लिए की गई वास्तविक लागत। इसे अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं से उस पर अर्जित ब्याज के साथ ऐसी दर पर वसूल किया जा सकता है, जो कानून में अनुमत हो, भले ही उत्तरदाताओं द्वारा जुर्माना राशि को वापस लेने या संशोधित करने के लिए किया गया प्रतिनिधित्व विचाराधीन हो। [पैरा 24] [152-डी-ई]पी

पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बनाम सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, (2007) 9 एससीसी 593; हरबंसलाल साहनिया एवं अन्य। बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। (2003) 2 एससीसी 107; भारत संघ एवं अन्य बनाम टांटिया कंस्ट्रक्शन प्रा. लिमिटेड (2011) 5 एससीसी 697; एम पी. राज्य कृषि उद्योग विकास निगम. और अन्य. बनाम जहान खान (2007) 10 एससीसी 88; व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई (1998) 8 एससीसी 1 - संदर्भित।

केस कानून संदर्भ

1970 (1) एससीआर 928	संदर्भित	पैरा 24
(2014) 9 एससीसी105	संदर्भित	पैरा 24
1990 (1) सप्ल.एससीआर 625	संदर्भित	पैरा 24
2007 (3) एससीआर 17	संदर्भित	पैरा 25
(2003) 2 एससीसी 101	संदर्भित	पैरा 25

2011 (5) एससीआर 397	संदर्भित	पैरा 25
2007 (9) एससीआर 715	संदर्भित	पैरा 25
1998 (2) सप्ल.एससीआर 359	संदर्भित	पैरा 25

सिविल अपीलिय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 9732/2016

डब्ल्यू. पी. (सी) संख्या 1 093/2006 में उड़ीसा उच्च न्यायालय, कटक के दिनांक 07.11.2012 के निर्णय और आदेश से।

गौरव बनर्जी, वरिष्ठ वकील, के.एन. मधुसूदनन के.एन., टी.जी. नारायणन नायर, एस.ए. हसीब, साहिल टैगोत्रा, अपीलकर्ताओं के लिए अधिवक्ता।

राकेश द्विवेदी, वरिष्ठ अधिवक्ता, अरुणाभ चौधरी, अनुपम लाल दास, वैभव तोमर, सुश्री श्रुति चौधरी, कर्मा दोरजी, अनिरुद्ध सिंह और सुश्री बरना चौधरी, प्रतिवादी के लिए अधिवक्ता।

न्यायालय का निर्णय न्यायाधीश ए. एम. खानविलकर द्वारा सुनाया गया।

1. अनुमति दी गई।

2. यह अपील रिट याचिका (सिविल) संख्या 1093/2006 में कटक में उड़ीसा उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के 7 नवंबर 2012 के फैसले को चुनौती देती है।

3. संक्षेप में कहा गया है, 2 दिसंबर 2002 को अपीलकर्ताओं ने अन्य बातों के साथ-साथ लखनपुर में विभिन्न ओपन कास्ट परियोजनाओं में "सरफेस माइन्स" को भर्ती के आधार पर तैनात करके कोयला/कोयला माप स्ट्रेटा (सीएमएस) के निष्कर्षण और हस्तांतरण के काम के लिए निविदाएं आमंत्रित करने के लिए नोटिस जारी किया था।

उत्तरदाताओं को कथित अनुबंध के लिए रु. 17/- प्रति घन मीटर की बोली लगाने पर सबसे कम बोली लगाने वाला घोषित किया गया था। उत्तरदाताओं के पक्ष में 4 अप्रैल, 2003 को एक आशय पत्र जारी किया गया था जिसे उत्तरदाताओं ने 14 अप्रैल, 2003 को स्वीकार कर लिया था। 23 अप्रैल, 2003 को उत्तरदाताओं के पक्ष में कार्य आदेश जारी किया गया था और 26 मई 2003 को पार्टियों के बीच एक औपचारिक समझौता निष्पादित किया गया था। समझौते के प्रासंगिक खंड खंड 2 से 5 हैं जो निम्नानुसार हैं:

"2) समय को अनुबंध के सार में से एक माना जाएगा और अनुबंध के पूरा होने का समय एलओएल जारी होने की तारीख से 16.04.2003 से गिना जाएगा, जिस पर ठेकेदार

ने उस समय सहमति व्यक्त की थी, जब उनकी निविदा स्वीकार कर ली गई और अनुबंध 15.04.2004 तक पूरा हो जाएगा, बशर्ते कि प्रबंधन द्वारा पर्याप्त चेहरा उपलब्ध कराया गया हो।

3) 49,50,000 घन मीटर की मात्रा के लिए एक वर्ष की अवधि के लिए 17.00 रुपये प्रति घन मीटर की दर से 8,41, 5 0.000.00 रुपये की राशि के लिए कार्य आदेश पहले ही जारी किया जा चुका है।

4) ठेकेदार कंपनी के निर्देशानुसार सरफेस माइनर को अन्य ओसीपी में फिर से तैनात करेगा।

5) निविदा की गई मात्रा को +/- 30% तक कम या बढ़ाया जा सकता है। गारंटी में इस तरह के बदलाव के लिए कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा, चाहे बढ़ोतरी हो या कमी।
निविदाकार को 45 दिनों के नोटिस के भीतर 30% अतिरिक्त दैनिक मात्रा पर मशीन की क्षमता बढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए। (जोर दिया गया)

4. चूंकि समझौता निविदा दस्तावेज़ के नियमों और शर्तों को संदर्भित करता है, हम उपयोगी रूप से उसमें संबंधित खंडों का उल्लेख कर सकते हैं।

"11.0 निर्धारित मात्रा सीमा और दर में भिन्नता

"मात्रा की अनुसूची के अनंतिम में दी गई मात्रा का उद्देश्य कार्य की सीमा को इंगित करना और निविदा के लिए एक समान आधार प्रदान करना है और इसमें वृद्धि या चूक से कोई भी बदलाव अनुबंध को रद्द नहीं करेगा।

निविदा की गई मात्रा को 30% तक घटाया या बढ़ाया जा सकता है। मात्रा में ऐसे परिवर्तन के लिए कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा, चाहे वृद्धि हो या कमी। अतिरिक्त बड़ी हुई मात्रा प्राप्त करने के लिए निविदाकार को 45 दिन पहले मशीन की क्षमता बढ़ाने की स्थिति में होना चाहिए।

यदि अतिरिक्त परिवर्तित या प्रतिस्थापित कार्य में कार्य की कोई भी वस्तु शामिल है जिसके लिए अनुबंध में कोई "दर निर्दिष्ट नहीं है, तो ऐसी वस्तु के लिए" दर "कंपनी मुख्यालय द्वारा निम्नलिखित तरीके से निर्धारित की जाएगी:

-

दर कंपनी में दिए गए कार्य के समान या लगभग समान मद के लिए दर से ली जाएगी, या

दर ठेकेदार द्वारा दावा की गई दर के विश्लेषण द्वारा समर्थित कार्य की ऐसी वस्तु के लिए ठेकेदार द्वारा दावा की गई दर

से ली जाएगी। कंपनी मुख्यालय द्वारा निर्धारित की जाने वाली दर को लाभ के प्रतिशत और ओवरहेड को ध्यान में रखते हुए दस प्रतिशत से अधिक या बाजार दर के आधार पर उचित माना जा सकता है। यदि कोई उस समय प्रचलित था जब कार्य किया गया था।

हालाँकि, प्रभारी अभियंता लिखित में नोटिस देकर निर्देश को रद्द करने और परिस्थितियों के तहत उचित समझे जाने वाले तरीके से काम करने की व्यवस्था करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में दरों का निपटान न होने की दलील देकर काम को निलंबित नहीं करेगा।

मूल रूप से अनुबंधित कार्य को पूरा करने का समय कंपनी द्वारा उसी अनुपात में बढ़ाया/घटाया जाएगा कि अतिरिक्त/घटा हुआ कार्य (मूल्य में) मूल अनुबंधित कार्य (मूल्य में) के बराबर है जैसा कि प्रभारी अभियंता द्वारा मूल्यांकन और प्रमाणित किया जा सकता है।

कंपनी को अपने प्रभारी इंजीनियर या उसके प्रतिनिधि के माध्यम से, कंपनी की ओर से, किसी अन्य कारण से कार्य के किसी भी हिस्से को छोड़ने की शक्ति होगी और ठेकेदार बदले हुए अभियंता को दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य

करने के लिए बाध्य होगा। इन आधारों पर ठेकेदार द्वारा अतिरिक्त शुल्क/उम्र के लिए कोई दावा नहीं किया जाएगा।

किसी भी विचलन के आदेश दिए जाने की स्थिति में, जो ठेकेदार की राय में अनुबंध के मूल दायरे और प्रकृति को मौलिक रूप से बदल देता है, ठेकेदार किसी भी परिस्थिति में काम पर खर्च नहीं करेगा, चाहे वह मूल हो या परिवर्तित या प्रतिस्थापित और विचलन की प्रकृति या भुगतान की जाने वाली दर के संबंध में विवाद/असहमति को कंपनी के साथ अलग से हल किया जाएगा।

13. अनुबंध पूरा करने का समय

समय अनुबंध का सार है. कार्य की संविदात्मक अवधि एनआईटी/एलओआई समझौते में निर्दिष्ट होगी। सभी स्थानों पर आशय पत्र जारी होने के 60 दिनों के भीतर काम शुरू हुआ माना जाएगा और एलओआई जारी होने की तारीख से 61वें दिन से दैनिक आवंटित मात्रा का 100% निष्पादित करने में सक्षम होना चाहिए।

ए/सी बिल पर समझौते को 1 के रिलीज होने से पहले निष्पादित किया जाना चाहिए।

एलओआई जारी होने के 61वें दिन से वांछित मात्रा तक पहुंचने में विफलता के लिए, ठेकेदार कमी मात्रा के लिए राशि का 20% यानी (कमी मात्रा x प्रदान की गई दर x 20%) की दर से दंड के लिए उत्तरदायी होगा।

ठेकेदार को एक दिन में तीन शिफ्टों और वर्ष के सभी कार्य दिवसों में लगातार काम करने के लिए तैयार रहना चाहिए:

यदि ठेकेदार, वैध कारण के बिना, एलओआई जारी होने की तारीख से 60 दिनों के भीतर कार्य का निष्पादन शुरू करने में चूक करता है या आशय पत्र जारी करने की निर्दिष्ट तिथि के भीतर काम पूरा करने में विफल रहता है, मात्रा की अनुसूची के अनुसार अंतिम आउटपुट देने के लिए आवश्यक मात्रा, कंपनी किसी अन्य अधिकार या उपाय पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ठेकेदार को लिखित रूप में 15 दिन का नोटिस देकर, उसके द्वारा जमा की गई बयाना राशि जब्त करने के लिए और अनुबंध समाप्त करने के लिए स्वतंत्र होगी।

..... ..

14.0 समापन तिथि का विस्तार

जैसा कि यहां बताया गया है, देरी का कारण बनने वाली किसी भी घटना के घटित होने पर, ठेकेदार क्षेत्र के सीजीएमआईजीएम को समय विस्तार के लिए आवेदन करेगा।

क) असामान्य रूप से खराब मौसम

बी) आग से गंभीर हानि या क्षति

ग) कार्य निष्पादन को प्रभावित करने वाला नागरिक हंगामा, हड़ताल या तालाबंदी

घ) कार्यबल या साइट की अनुपलब्धता जिसकी आपूर्ति करना कंपनी की जिम्मेदारी है।

ई) कोई अन्य कारण जो कंपनी के विवेक पर ठेकेदार के नियंत्रण से परे है।

ठेकेदार ऐसी घटना होने के 14 दिनों के भीतर अवधि बताते हुए देरी को रोकने के लिए कंपनी से लिखित रूप में समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकता है, जिसके लिए विस्तार वांछित है, कंपनी अनुरोध की पात्रता पर विचार करते हुए कार्य पूरा करने के समय में उचित और उचित विस्तार दे सकती है। इस तरह के विस्तार के बारे में कंपनी द्वारा ऐसे

अनुरोध की प्राप्ति की तारीख से 1 महीने के भीतर प्रभारी इंजीनियर के माध्यम से ठेकेदार को लिखित रूप में सूचित किया जाएगा।

30.0 डिफॉल्ट और जुर्माना

30.1 हानि या क्षति

कंपनी द्वारा किए गए किसी भी नुकसान या क्षति के लिए एवी व्यय ठेकेदार से वसूली योग्य होगा, चाहे वह पूरी तरह से या आंशिक रूप से हो, यदि क्षति के लिए ऐसा व्यय ठेकेदार की ओर से किसी लापरवाही या विफलता के कारण प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से हुआ हो।

30.2. यांत्रिक उत्खनन और लोडिंग में कमी जुर्माना

तिमाही की औसत दैनिक मात्रा 30 जून, 30 सितंबर, 31 दिसंबर और 31 मार्च को समाप्त होने वाली तिमाही के कार्य दिवसों द्वारा पारस्परिक रूप से सहमत त्रैमासिक आवंटित मात्रा को विभाजित करके निकाली जाएगी, किसी तिमाही की औसत दैनिक मात्रा वर्ष की संविदा अवधि की औसत दैनिक मात्रा के अनुरूप होनी चाहिए।

यदि ठेकेदार सहमत प्रगति चार्ट के अनुसार प्रगति की दर का अनुपालन करने में विफल रहता है तो ठेकेदार मात्रा पर जुर्माना देने के लिए उत्तरदायी होगा, जिसके द्वारा ठेकेदार को आवंटित दर के 20% की दर से आवंटित त्रैमासिक मात्रा से कम हो गया है।

एनआईटी (100 मिमी आकार) के अनुसार उत्पादन आकार के कोयले की विफलता के लिए, संपर्ककर्ता इतनी बड़ी मात्रा के लिए दी गई दर के 20% की दर से दंड के लिए भी उत्तरदायी होगा।

कमी का जुर्माना चालू बिल से समवर्ती रूप से वसूल किया जाएगा जिसे वार्षिक रूप से समायोजित किया जाएगा, बशर्ते कि कुल जुर्माना (वार्षिक कमी मात्रा x दर) के 20% तक सीमित हो।

30.3 जुर्माने की छूट

कंपनी अपने विवेक के आधार पर मामले की योग्यता के आधार पर ठेकेदार से प्राप्त अनुरोध पर जुर्माने का भुगतान पूर्ण या आंशिक रूप से माफ कर सकती है, यदि संपूर्ण कार्य अनुबंध में निर्दिष्ट तिथि के भीतर या जुर्माना लगाए बिना स्वीकृत विस्तारित अवधि के भीतर पूरा हो जाता है।

31.0. विवाद का निपटारा

अनुबंध में अन्यथा प्रावधान किए जाने के अलावा, यहां पहले उल्लिखित दायरे, विनिर्देशों और निर्देशों के अर्थ और किसी भी अन्य प्रश्न से संबंधित सभी प्रश्न और विवाद, किसी भी तरह से अनुबंध, निर्देश, आदेश या इन शर्तों से संबंधित या अन्यथा कार्यों या निष्पादन या निष्पादन में विफलता के संबंध में किसी भी तरह से सही मामले या चीज का दावा करें। चाहे कार्य की प्रगति के दौरान या उसके पूरा होने या त्यागने के बाद उत्पन्न हो, कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत किसी अन्य व्यक्ति को भेजा जाएगा।

यह भी अनुबंध की एक शर्त है यदि ठेकेदार कंपनी से सूचना प्राप्त होने के 90 दिनों के भीतर लिखित रूप में किसी भी दावे के लिए कोई मांग नहीं करता/नहीं करता है। बिल भुगतान के लिए तैयार है या भुगतान प्राप्त करने की तारीख, जो भी पहले हो, ठेकेदार का दावा माफ कर दिया गया माना जाएगा और पूरी तरह से वर्जित है और कंपनी को इन दावों के संबंध में अनुबंध के तहत सभी देनदारियों से मुक्त कर दिया जाएगा।" (जोर दिया गया)

5. उत्तरदाताओं ने लखनपुर में सतही खनिकों का काम शुरू किया और फरवरी 2004 के अंत तक आवंटित मात्रा का लगभग 70% पूरा कर लिया। दिनांक 3 फरवरी 2004 के पत्र के माध्यम से उत्तरदाताओं द्वारा सामना की गई वित्तीय समस्याओं के कारण, उन्होंने अपीलकर्ताओं से एनआईटी के सामान्य नियमों और शर्तों के खंड 11 के तहत, दी गई मात्रा के 30% तक मात्रा को कम करने की शक्ति का उपयोग करके अनुबंध को बंद करने की अनुमति देने का अनुरोध किया; और शेष कार्य के लिए नये सिरे से निविदा जारी करने को कहा। अपीलकर्ताओं ने उक्त अनुरोध को स्वीकार नहीं किया और उत्तरदाताओं को दिनांक 6 फरवरी 2004 के पत्र के माध्यम से सूचित किया, जिसमें कहा गया था कि समझौता दिए गए मूल्य के 100% तक अनुबंध को निष्पादित करने के लिए है और समान नियमों और शर्तों पर अतिरिक्त 30% मात्रा को निष्पादित करने का प्रावधान है। उत्तरदाताओं ने 9 मई 2004 के पत्र द्वारा अपीलकर्ताओं से शेष अनुबंध को पूरा करने की समय सीमा 15 जुलाई 2004 तक बढ़ाने का अनुरोध किया क्योंकि अनुबंध की अवधि केवल 15 अप्रैल 2004 तक थी। उक्त पत्र इस प्रकार है:

अनुलग्नक-पी 8

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि.,

पी.ओ. धनसार

पी.ओ.जोराबागा

धनबाद- 828106 (झारखंड)

वाया बेलपहाड़

फ़ोन: 0326-307161/70741

जिला:झारसुगुडा (उड़ीसा)

फैक्स: 0326 303294

फ़ोन: 06645 -233222

ई-मेल-decopl.dte.vsnl.net.in

संदर्भ संख्या: डेको/एनआईटी 27612004

दिनांक: 09. 05.2004

को

मुख्य महाप्रबंधक

लखनपुर क्षेत्र

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

(उचित माध्यम से)

विषय: कार्य आदेश संख्या के तहत लखनपुर क्षेत्र के लखनपुर ओसीपी (एनआईटी-276) में सरफेस माइनर को किराये पर तैनात कर कोयला/कोयला माप स्ट्रेटा के निष्कर्षण एवं स्थानांतरण का कार्य। एमसीएलआईसीजीएम/एलकेपीई एसओ(एम)/सुर.माइनर/2003-041001 दिनांक 23.04.2003।

प्रिय महोदय,

प्रबंधन को इस बात की पूरी जानकारी है कि काम के लिए 171 रुपये प्रति घन मीटर की निविदा दर अब तक की सबसे कम और पूरी तरह से अव्यवहारिक है। हम भारी घाटे में इस दर पर काम कर रहे हैं।

हमने 16.04.2003 को लगभग मानसून के आगमन पर ही काम शुरू कर दिया था और गर्मी की चेतावनी और सुबह 11.00 बजे से शाम 4.00 बजे के बीच परिवहन प्रतिबंध के कारण हम प्रगति में तेजी नहीं ला सके। इसके बाद भारी बारिश हुई, जिसके परिणामस्वरूप खराब, जल-जमाव और फिसलन भरी सड़क के कारण रोक की कम आपूर्ति हुई। हमारे नियंत्रण से परे इन सभी परिचालन खतरों के साथ, हम 31.03.2004 तक 34.74 लाख घन मीटर पूरा कर सके।

चूँकि हमारा वित्तीय घाटा दिन-ब-दिन बढ़ता जा रहा था, हमने 70% काम पूरा करने के बाद काम को बंद करने का अनुरोध किया था, लेकिन जीएम (टीसी) ने अपने पत्र संख्या 1251 दिनांक 26.03.2004 के माध्यम से इस पर सहमति नहीं जताई।

इसलिए, संविदात्मक दायित्व के तहत होने के कारण हमारे पास 15.07.2004 तक समय विस्तार के लिए आवेदन करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था, आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त मात्रा के पूरा होने

के साथ ही अनुबंध को समाप्त मान लिया जाए क्योंकि हम आगे का नुकसान सहन करने में असमर्थ हैं।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

एसडी/-

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए।"

6. उत्तरदाताओं के इस अनुरोध पर बोर्ड की 68 वीं बैठक में अपीलकर्ताओं द्वारा विचार किया गया। जुर्माना लगाने का अधिकार सुरक्षित रखते हुए तीन महीने का समय बढ़ाया गया। उत्तरदाताओं को दिनांक 1 जून 2004 के पत्र द्वारा तदनुसार सूचित किया गया था। इस निर्णय के परिणामस्वरूप, अनुबंध की अवधि उन्हीं नियमों और शर्तों पर 15 जुलाई 2004 तक बढ़ा दी गई थी जिन पर सहमति व्यक्त की गई थी। चूंकि अनुबंध की अवधि 15 जुलाई 2004 तक विद्यमान थी। अपीलकर्ताओं ने 11 जून 2004 को एक अनुमोदन आदेश जारी किया, जिसमें अगली निविदा दर की मौजूदा दर पर 30% अतिरिक्त मात्रा यानी 14.8 लाख घन मीटर या जो भी कम हो, 252.42 लाख रुपये की वृद्धि की गई। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने जे जे जून 2004 के पत्र द्वारा दोहराया कि अनुबंध को बंद माना जाए - क्योंकि वे जून 2004 तक अनुबंध में निर्दिष्ट मात्रा को पूरा करने के कगार पर थे। उक्त पत्र इस प्रकार है:

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लि.,

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि.,

पी.ओ. धनसार

पी.ओ.जोराबागा

धनबाद- 828106 (झारखंड)

वाया बेलपहाड़

फ़ोन: 0326-307161/70741

जिला:झारसुगुडा (उड़ीसा)

फैक्स: 0326 303294

फ़ोन: 06645 -233222

ई-मेल-decopl.dte.vsnl.net.in

को

मुख्य महाप्रबंधक

लखनपुर क्षेत्र

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड,

विषय: एनआईटी नं. 276-एमसीएल के लखनपुर ओसीपी में एचआर/एनजी आधार पर सरफेस माइनर की तैनाती करके कोयला/कोयला माप स्ट्रेटा का निष्कर्षण/चालू और स्थानांतरण

प्रिय महोदय,

हम आपको सूचित करना चाहेंगे कि 49.50 लाख सीयूएम की ऑर्डर मात्रा पूरी होने के कगार पर है, और उम्मीद है कि यह मात्रा 15.06.2004 तक पूरी हो जाएगी।

इस संबंध में कृपया हमारे पत्र संख्या डेको/एनआईटी-276/2004 दिनांक 09.05.2004 का संदर्भ लें जिसके तहत हमने आपसे 49.50 लाख घन मीटर की मात्रा के पूरा होने के साथ अनुबंध को बंद मानने का अनुरोध किया था। अपना अनुरोध दोहराते हुए हम आपको सूचित करेंगे कि हमें मशीन बंद करने के लिए मजबूर होना पड़ सकता है क्योंकि यह परेशानी दे रही है और धन की भारी कमी के कारण हम मशीन की मरम्मत करने में सक्षम नहीं हैं।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

एसडी/-

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के लिए।

प्रतिलिपि: 1) निदेशक (तकनीकी) एमसीएल, बुर्ला,

2) महाप्रबंधक, लखनपुर क्षेत्र। "

7. उत्तरदाताओं ने 61 जुलाई 2004 को एक अन्य पत्र द्वारा वित्तीय कठिनाई के कारण अनुबंध को बंद करने की मांग करते हुए कहा कि वे अपना परिचालन वापस ले रहे हैं। हालाँकि, अपीलकर्ताओं ने 7 जुलाई 2004 के पत्र द्वारा उत्तरदाताओं से अनुबंध के तहत सौंपे गए शेष कार्य को जारी रखने का आह्वान किया जो अभी भी जारी था; और यह भी नोट किया कि उत्तरदाताओं ने तब तक 130% में से केवल 105% अनुबंध कार्य पूरा किया था। उक्त संचार इस प्रकार है:

"अनुलग्नक-पी 12

केवल संबलपुर न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

कॉर्पोरेट कार्यालय

मुख्य महाप्रबंधक का कार्यालय

एम.सी.एल. कॉम्प्लेक्स

लाखनपवररिया

जागृति विहार

पी. 0. बंधबहाल - वाया: बेलपहाड़

बुर्ला - 768018

जिला: झारसुगुडा, पिन 768217

जिला: संबलपुर (उड़ीसा) फोन: 33202, एसटीडी कोड: 06645

संदर्भ संख्या MCLICGMILKPAISO(M)/932

दिनांक: 07.07.2004

को

मिस धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड लिमिटेड

साइट कार्यालय: पी.ओ. जोराबगा, वाया - बेलपहाड़।

जिला: झारसुगुडा (उड़ीसा)

पिन: 768217.

संदर्भ- {1} लखनपुर ओसीपी (एनआईटी) में किराये के आधार पर 'सतह खनिकों' को तैनात करके कोयला/कोयला माप स्तर के निष्कर्षण/हस्तांतरण के लिए कार्य आदेश संख्या MCLICGMILKPAISOM{M)/सर माइनर/2003-041001 दिनांक 23.04.2003 -276).

विषय: लखनपुर ओसीपी में स्वफेस माइनर कार्य का अनुबंध (एनआईटी नंबर 276 के तहत)

प्रिय महोदय,

कृपया उपरोक्त विषय पर अपना पत्र संख्या DECO/NJT-27612004

दिनांक 6.07.2004 देखें।

यह आपके ध्यान में लाया जाता है कि कार्य आदेश के खंड संख्या 2 के अनुसार जो अनुबंध का हिस्सा है, निविदा की मात्रा 30% तक बढ़ाई जा सकती है और आज तक केवल 105% (लगभग) इस तरह की भिन्नता के लिए कंपनी पर कोई दावा नहीं किया जाएगा। .) प्रदान की गई राशि का निष्पादन आपके द्वारा कर दिया गया है। उपरोक्त कार्य के लिए नए अनुबंध को अंतिम रूप देने के लिए एमसीएलएचक्यू से आज तक कोई संचार नहीं हुआ है।

ऐसी स्थिति में आपसे अनुरोध है कि 30% अतिरिक्त मात्रा के पूरा होने तक लखनपुर ओसीपी में सतही खनिक का संचालन जारी रखें। इस स्तर पर स्वफेस माइनर के परिचालन को वापस लेने से हमारे पिट हेड ग्राहक {ओपीजीसी) और अन्य लिंकेज ग्राहकों को कोयले का प्रेषण गंभीर रूप से प्रभावित होगा, जिससे कंपनी का नाम खराब हो रहा है।

धन्यवाद,

आपका विश्वासी,

महाप्रबंधक

लखनपुर क्षेत्र

प्रतिलिपी :

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक; एमसीएल बुर्ला

निदेशक (टी), एमसीएल, बुर्ला

महाप्रबंधक (टीसी), एमसीएल मुख्यालय, बुर्ला

स्लैफ़ अधिकारी (खनन) एलकेपीए"

8. हालाँकि, उत्तरदाताओं ने 15 जुलाई 2004 और 12 जुलाई 2004 के पत्रों के माध्यम से अनुबंध को बंद करने की अनुमति देने के लिए अपीलकर्ताओं से अपना अनुरोध नवीनीकृत किया। उत्तरदाताओं ने अंततः 15 जुलाई 2004 को अपीलकर्ताओं को लिखा जो इस प्रकार है:

“अनुलग्नक-P15

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्रा. लि.,

पी.ओ. धनसार

पी.ओ.जोराबागा

धनबाद- 828106 (झारखंड)

वाया बेलपहाड़

फ़ोन: 0326-307161/70741

जिला:झारसुगुडा (उड़ीसा)

फैक्स: 0326 303294

फ़ोन: 06645 -233222

ई-मेल-decopl.dte.vsnl.net.in

प्रसंग संख्या-डेको/एनआईटी 276/2004

दिनांक: 15.07.2004

को

महाप्रबंधक,

लखनपुर क्षेत्र, एमसीएल,

विषय: एनआईटी नं.276 जी के अंतर्गत लखनपुर ओसीपी में सरफेस माइनर का काम बंद करना

प्रिय महोदय,

हमारे पत्र संख्या DECO/NIT/2004 दिनांक 12.07.2004 की एक प्रति, जो CMD MCL बुर्ला को संबोधित है और इसकी प्रतियाँ D(T) और GM(TC), MCL मुख्यालय को भी आपकी जानकारी के लिए संलग्न है।

जैसा कि अधिसूचित किया गया है, आपको सूचित किया जाता है कि हम 16.07.2004 (एफएन) से लखनपुर ओसीपी में काम बंद कर रहे हैं और परिचालन बंद कर रहे हैं। यह उल्लेख करना अप्रासंगिक नहीं होगा कि हम अपनी गैर-आर्थिक दुर्दशा के कारण 100% काम पूरा करने के बाद निष्पादन को छोड़ने का इरादा व्यक्त कर रहे थे और अगले उपाय की व्यवस्था करने के लिए प्रबंधन के साथ सहयोग करने के लिए निष्पादन जारी रख रहे थे।

ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि लखनपुर ओसीपी के उत्पादन कार्यक्रम में कोई बाधा न आए।

हालाँकि हम अपने पत्रों के बारे में कोई सूचना या प्रबंधन से कोई सहानुभूतिपूर्ण निर्णय नहीं प्राप्त कर सके। इसी बीच 15.07.2004 को अनुबंध अवधि भी समाप्त हो गयी।

उपरोक्त स्थिति को देखते हुए हमारे पास अनुबंध की पूरी अवधि तक काम करने के बाद परिचालन से हटने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं है।

इसलिए आपसे अनुरोध है कि कृपया 15.07.2004 को अंतिम माप लें और अनुबंध को अंतिम रूप दें।

आपको धन्यवाद देता हूँ और हर समय हमारे सर्वोत्तम सहयोग का आश्वासन देता हूँ।

आपका विश्वासी,

एसडी/-

धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड

प्रतिलिपि :

1. सीएमडी, एमसीएल, बुर्ला फैंक्स नंबर 0663 -2432066/2542366

2. डी(टी), एमसीएल, बुर्ला, फ़ैक्स नंबर 0663-2542509

3. जीएम (टीसी), एमसीएल, बुर्ला, फ़ैक्स नंबर 0663-25426291"

9. चूंकि उत्तरदाताओं ने पहले ही अपीलकर्ताओं को पूर्ण अनुबंध अवधि के बाद संचालन से हटने के अपने इरादे के बारे में सूचित कर दिया था, अपीलकर्ताओं द्वारा एक नई निविदा प्रक्रिया शुरू की गई थी जो तीसरे पक्ष (सैनिक खनन और संबद्ध सेवाओं) के पक्ष में एक पत्र के साथ समाप्त हुई, लेकिन 31.50 रुपये प्रति घन मीटर की ऊंची दर पर।

10. 26 मई 2003 के अनुबंध के तहत निष्पादित कार्य के लिए उत्तरदाताओं द्वारा प्रस्तुत बिलों पर अपीलकर्ताओं के बोर्ड ने अपनी 72 वीं बैठक में विचार किया। उक्त बैठक में लिए गए निर्णय की सूचना उत्तरदाताओं को दिनांक 8 दिसंबर 2014 के पत्र द्वारा दी गई, जो इस प्रकार है:

"अनुलग्नक आर/9

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी)

पी.ओ. -जागृति विहार, बुर्ला, जिला। संबलपुर-768020 (उड़ीसा)

ग्राम: सैम्बकोल, : फ़ैक्स: (0663)2542770

फोन: पीबीएक्स:- (0663) 2542461 से 2542469

Ref.No.MCUSBP/GM(TC)/200411047 दिनांक. 08.12.2004

को,

महाप्रबंधक,

लखनपुर क्षेत्र

प्रिय महोदय,

कृपया इसके साथ संलग्न मेसर्स धनसर इंजीनियरिंग (पी) लिमिटेड को एनआईटी - 276 के तहत कुल अनुबंधित मात्रा का 130% गैर-प्रदर्शन के लिए 20.00 लाख रुपये की बयाना जमा राशि को जब्त करने के माध्यम से जुर्माना लगाने के संबंध में 27 नवंबर, 2004 को कोलकाता में आयोजित एमसीएल के निदेशक मंडल की 72 वीं बैठक के ड्राफ्ट मिनट्स से उद्धरण की एक प्रति प्राप्त करें। प्रासंगिक उद्धरण नीचे संलग्न है: -

"बोर्ड ने इस विषय पर विस्तार से विचार-विमर्श किया और एजेंडा नोट में उजागर किए गए तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए और विचार-विमर्श के दौरान दिए गए स्पष्टीकरण को मान्यता देते हुए निर्णय लिया कि एनआईटी-276 के तहत कुल अनुबंधित मात्रा का 130% गैर-प्रदर्शन के लिए एमआईएस धनसर इंजीनियरिंग प्राइवेट लिमिटेड पर

अनुबंध के प्रावधानों के संदर्भ में एजेंडा नोट में प्रस्तावित जुर्माना लगाया जाएगा।"

एजेंडा नोट में प्रस्तावित

खंड संख्या 16- (बयाना राशि की जब्ती)

ठेकेदार खंड संख्या 16(a) और 16(d) के तहत जमा राशि जब्त करने के लिए उत्तरदायी है, जो इस प्रकार है:-

[6(2) प्रस्ताव की वैधता अवधि के दौरान अपना प्रस्ताव वापस ले लेता है।

में 6(ए) उसके नियमों और शर्तों के अनुसार आदेश को निष्पादित करने में विफल रहता हूँ।

वर्तमान मामले में ईएमडी रु. 20.00 लाख.

खण्ड क्रमांक 30.2 (यांत्रिक उत्खनन एवं लोडिंग में कमी जुर्माना)

-अनुबंध मात्रा का 130% -63,70,000.00 Cu.m.

-निष्पादित अंतिम मात्रा-53,49,437.55 Cu.m.

-निष्पादित की जाने वाली शेष मात्रा- 10,20,562.45 Cu.m.

-कार्य दर -रु. 17.00 प्रति घन मी.

-कार्य दर का 20% रु. 3.40 प्रति घनमीटर।

-निष्पादन न करने पर देय जुर्माना

-130% तक मात्रा रु. 34,69,91 एल.ओ.ओ

ये दंड प्रबंधन द्वारा लिए गए निर्णय के आधार पर व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से लगाए जा सकते हैं। जुर्माना लगाने का निर्णय इस पृष्ठभूमि पर किया जा सकता है कि बहुत कम दर पर काम करने वाले ठेकेदार ने भारी नुकसान उठाने के बावजूद 08.4 7% निष्पादित किया है और केवल तभी वापस लिया है जब नया अनुबंध समाप्त हो गया है, यह सुनिश्चित करते हुए कि उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ है।

आपका विश्वासी

एसडी/- पढ़ने योग्य

महाप्रबंधक (टीसी)

संलग्नक: उपरोक्तानुसार"

11. अपीलकर्ताओं के बोर्ड ने अपनी 78111 बैठक में उत्तरदाताओं द्वारा शेष अनुबंध कार्य के गैर-निष्पादन के लिए जुर्माना लगाने का निर्णय लिया और उस कार्य को उच्च दर पर तीसरे पक्ष को आवंटित करने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई वित्तीय हानि भी शामिल की। उस निर्णय के संदर्भ में,

अपीलकर्ताओं द्वारा जे'डी नवंबर 2005 को दंड की वसूली के लिए एक अनुमोदन आदेश जारी किया गया था जो इस प्रकार है:

"अनुलग्नक-19

महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की एक सब्सिडी)

पी.ओ. - जागृति विहार

बुर्ला - 768018

जिला: संबलपुर-768020 (उड़ीसा)

ग्राम: सैम्बकोल,; फैक्स: (0663) 2542770

फ़ोन: PBX:- 2542461 to 2542470

संदर्भ संख्या MCLISBPIGM(TC)/200511100 दिनांक: 03.11.2005

अनुमोदन आदेश

विषय: एनआईटी-276 (डीआई; 01.12.2002) के तहत "सरफेस माइन्स" को किराये के आधार पर तैनात करके "कोयला/कोयला माप स्तर के निष्कर्षण और हस्तांतरण" के कार्य के लिए लखनपुर ओसीपी, लखनपुर

क्षेत्र में एमआईएस धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड पर जुर्माना लगाना।

"तैनाती द्वारा कोयला/कोयला माप स्ट्रेटा के निष्कर्षण और स्थानांतरण" के कार्य के लिए मेसर्स धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को एनआईटी -276 दिनांक 02.12.2002 के तहत जुर्माना लगाने के मुद्दे की जांच करने के लिए समिति की सिफारिश पर सरफेस माइनर्स" को लखनपुर ओसीपी, लखनपुर क्षेत्र में किराये के आधार पर, डी(टी) ! डी(एफ)आईडी(पी)/सीएमडीआईएमसीएल द्वारा पीजीआरजी किया गया है। एमसीएल बोर्ड ने 27.10.2005 को आयोजित अपनी 78 वीं बैठक में मद संख्या 78.सी/20 के तहत मेसर्स धनसार इंजीनियरिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड को अनुबंध के प्रावधान के संदर्भ में जुर्माना लगाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 'एनआईटी-76 के तहत संपर्क किए गए कुल संपर्कों में से 130% के गैर-प्रदर्शन के कारण (दिनांक: 02.12.2002) समझौते के खंड - 30. 1 (हानि या क्षति) के तहत 1,57,40,655.22 रुपये (एक करोड़ सत्तावन लाख अड़तालीस हजार छह सौ पचपन रुपये मात्र) की राशि के लिए।

एसडी/- महाप्रबंधक (टीसी)

वितरण:

1. जीएम लखनपुर एरिया

2. सीजीएम(एफ) एमसीएल, मुख्यालय
3. टीएस से सीएमडी, एमसीएल
4. टीएस से डी(टी), एमसीएल
5. सचिव. डी(एफ), एमसीएल को
6. मंजूरी आदेश फ़ाइल"

12. व्यथित होकर, उत्तरदाताओं ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका दायर की और निम्नानुसार प्रार्थना की:

"प्रार्थना

इन परिस्थितियों में, यह प्रार्थना की जाती है कि आपका आधिपत्य विपक्षी दलों को बुलाने के लिए सर्टिओरारी की प्रकृति में एक नियम एनआईएसआई जारी करने की कृपा करें। यह कारण बताने के लिए कि महानदी कोल फील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक (टीसी) द्वारा जारी अनुलग्नक-22 के माध्यम से दिनांक 08.12.2004 को विपक्षी पार्टी संख्या 2 पर जुर्माना लगाने वाले पत्र को क्यों रद्द नहीं किया जाएगा और यदि विपक्षी पार्टियां कारण बताने में विफल रहती हैं या अपर्याप्त कारण दिखाने पर उक्त नियम पूर्ण हो जाता है।

और

परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें विपक्षी दलों को याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी को 79,01,434.60 रुपये की राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए, जिसे विपक्षी दलों ने अवैध रूप से रोक रखा है।

और

परमादेश की प्रकृति में एक रिट जारी करें जिसमें विपक्षी दलों को प्रति वर्ष 18% की दर से ब्याज का भुगतान करने का निर्देश दिया जाए क्योंकि विपक्षी दलों ने 15.07.2004 से याचिकाकर्ता नंबर 1 कंपनी के 79,01,434.60 रुपये के बकाया को अवैध रूप से रोक रखा है।

और

ऐसे अन्य रिट/रिट, आदेश/आदेश, निर्देश/निर्देश जारी करें जिन्हें माननीय न्यायालय उचित एवं उचित समझे। और/या दयालुता के इस कार्य के लिए याचिकाकर्ता कर्तव्य के तहत हमेशा प्रार्थना करेगा। "

13. अपीलार्थियों द्वारा जवाबी हलफनामा दाखिल कर रिट याचिका का विरोध किया गया। अपीलकर्ताओं ने रिट याचिका की विचारणीयता के बारे में प्रारंभिक आपत्ति उठाई। योग्यता के आधार पर, अपीलकर्ताओं ने दावा किया कि उत्तरदाताओं के खिलाफ उठाई गई मांग अनुबंध के नियमों और शर्तों के अनुरूप थी और यदि उत्तरदाता इससे व्यथित थे तो वे समझौते के खंड 31 के तहत निपटान की प्रक्रिया का सहारा लेने के लिए स्वतंत्र थे।

उच्च न्यायालय की खण्डपीठ, हालाँकि, उत्तरदाताओं द्वारा दायर की गई रिट याचिका को इस निष्कर्ष पर स्वीकार कर लिया गया कि अनुबंध के खंड 5 के संदर्भ में अपीलकर्ताओं के लिए अनुबंध अवधि के अंत में उत्तरदाताओं को अतिरिक्त काम आवंटित करना स्वीकार्य नहीं था, जिसमें अनुबंध के तहत मात्रा में बदलाव के लिए 45 स्पष्ट दिनों का नोटिस देने की परिकल्पना की गई थी। वह नोटिस उत्तरदाताओं को केवल 11 जून 2004 को दिया गया था, भले ही विस्तारित अनुबंध अवधि 15 जुलाई 2004 को समाप्त होनी थी। न्यायालय ने माना कि, आश्चर्यजनक रूप से 5 जून 2004 को अनुबंध की अवधि बढ़ाने के बाद, 11 जून 2004 को छह दिनों के भीतर अपीलकर्ताओं ने अनुबंध की मात्रा 30% बढ़ाने का निर्णय लिया। वह सद्भावनापूर्ण कार्य नहीं था और अस्वीकार्य था। न्यायालय ने यह भी माना कि अपीलकर्ताओं ने इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि किन परिस्थितियों में निदेशक मंडल द्वारा जुर्माना लगाने का निर्णय लिया गया। न्यायालय ने आगे कहा कि उत्तरदाताओं ने 108.47% तक के अनुबंध को बहुत कम दर पर निष्पादित किया था, और उस संबंध में भारी नुकसान उठाया था। इसके अलावा, लखनपुर ओसीपी के लिए एक नया अनुबंध पहले ही दिया जा चुका था और अपीलकर्ताओं को उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ था। इन आधारों पर, डिवीजन बेंच ने निम्नलिखित शर्तों में रिट याचिका की अनुमति दी:

"16. तदनुसार, अनुबंध-22 के तहत महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड के महाप्रबंधक (टी.सी.) के दिनांक 8.12.2004 के पत्र, जिसमें कमी पर जुर्माना लगाने का प्रस्ताव था, और साथ ही जवाबी हलफनामे के अनुबंध-ए के तहत इसके अनुमोदन आदेश दिनांक 03.11.2005 को रद्द कर दिया गया है। . याचिकाकर्ता को देय बकाया राशि अनुबंध के समापन की तारीख यानी 16. 7.2004 से गणना की जाने वाली 8% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज के साथ तीस दिनों की अवधि के भीतर उसके पक्ष में जारी की जाए। इस न्यायालय के दिनांक 28.7.2009 के निर्देश के अनुसार याचिकाकर्ताओं द्वारा दी गई बैंक गारंटी को रद्द करने का निर्देश दिया जाता है और परिणामस्वरूप, निर्देश दिया जाता है कि इसे तुरंत याचिकाकर्ताओं को वापस कर दिया जाए। उपरोक्त शर्तों के साथ रिट याचिका स्वीकार की जाती है। कोई लागत नहीं।"

14. व्यथित होकर, अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है। इस न्यायालय ने 21 अप्रैल, 2013 को एक अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें अगले आदेश तक यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश दिया गया।

15. अपीलकर्ताओं के अनुसार उच्च न्यायालय ने रिट याचिका पर विचार करने में स्पष्ट त्रुटि की है। सबसे पहले, एक विशुद्ध रूप से संविदात्मक मामले के संबंध में और इससे भी अधिक जब अनुबंध के खंड 31 के तहत प्रभावकारी उपाय उत्तरदाताओं को उनकी शिकायत के निवारण के लिए उपलब्ध था। दूसरे, योग्यता के आधार पर उच्च न्यायालय ने

अनुबंध की शर्तों और विशेष रूप से अनुबंध के खंड 5 को गलत समझा और गलत तरीके से लागू किया है। हालाँकि, यदि अनुबंध के नियमों और शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं रह जाता है कि अपीलकर्ताओं के पास मूल अनुबंध अवधि को बढ़ाने का विवेक था; और उत्तरदाताओं के अनुरोध पर ऐसा करने पर, उत्तरदाता 151 जुलाई 2004 तक अनुबंध की शर्तों से बंधे थे। इसके अलावा, उस तारीख से पहले किसी भी समय, :: अपीलकर्ताओं के लिए अनुबंध की मात्रा को 30% तक कम करने या बढ़ाने के लिए खुला था। अनुबंध को पूरा करने में असमर्थता के लिए उत्तरदाताओं की एकमात्र दलील कम अनुबंध दर के कारण वित्तीय कठिनाई और अतिरिक्त नुकसान पर आधारित थी। इसे अनुबंध से बाहर निकलने पर कोई विचार नहीं किया जा सकता। मोरेसो, अतिरिक्त मात्रा आवंटित होने के बाद उत्तरदाता अतिरिक्त कार्य पूरा करने के लिए अतिरिक्त समय मांग सकते थे, यदि वे अनुबंध अवधि के भीतर इसे पूरा करने की स्थिति में नहीं थे। उस अनुरोध पर अपीलकर्ताओं द्वारा उचित रूप से विचार किया जा सकता था। उत्तरदाताओं ने ऐसा नहीं किया। इसके बजाय, उन्होंने केवल इसलिए परिचालन से हटने पर जोर दिया क्योंकि अनुबंध की दर उनके लिए सस्ती नहीं थी। परिणामस्वरूप, अपीलकर्ताओं को उत्तरदाताओं द्वारा अधूरे कार्य की अतिरिक्त मात्रा को तीसरे पक्ष को उच्च दर पर आवंटित करना पड़ा। तथ्य यह है कि अपीलकर्ताओं को उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ, इसका मतलब यह नहीं है कि अधूरे अतिरिक्त काम के लिए उच्च दर के भुगतान के कारण अपीलकर्ताओं को कोई वित्तीय

नुकसान नहीं हुआ। इसलिए, अपीलकर्ताओं को अधूरे अतिरिक्त काम के संबंध में दर के अंतर और उसके लिए दंड की वसूली करना उचित था। पार्टियों के बीच अनुबंध के नियमों और शर्तों के तहत यह एक वैध मांग थी।

16. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं का तर्क है कि प्रतिवादियों को मूल अनुबंध के अनुसार और विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर यानी 15 जुलाई 2004 तक अनुबंध को बंद करने की अनुमति न देना अपीलकर्ताओं की ओर से अनुचित था, इसके अलावा, उत्तरदाताओं को अधूरे अतिरिक्त काम के लिए उत्तरदायी नहीं बनाया जा सकता क्योंकि वह केवल 11 जून 2004 को आवंटित किया गया था, जिससे उत्तरदाताओं के पास उसे पूरा करने के लिए बहुत कम समय बचा था, जिसके लिए अपीलकर्ताओं को उन्हें दोषी ठहराना चाहिए.....। उत्तरदाताओं के अनुसार, उच्च न्यायालय का निष्कर्ष सही था कि समझौते के खंड 5 ने अपीलकर्ताओं को विस्तारित अनुबंध अवधि के अंत में 30% की सीमा तक अतिरिक्त मात्रा में काम आवंटित करने की अनुमति नहीं दी, जबकि 45 स्पष्ट दिनों का नोटिस अनिवार्य था। इसके अलावा, उच्च न्यायालय ने यह भी ध्यान में रखते हुए एक न्यायसंगत आदेश पारित किया है कि उत्तरदाताओं ने पहले ही भारी नुकसान उठाकर 108.4 7% अनुबंध कार्य निष्पादित कर लिया था, जो तथ्य उत्तरदाताओं को देय 17/- रुपये प्रति घन मीटर की दर के विरुद्ध 31.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से नये अनुबंध के निष्पादन से

प्रमाणित होता है। यह भी तर्क दिया गया है कि जुर्माना राशि की मांग एकतरफा और बिना किसी उचित कारण के है। वही अवैध है। इसलिए, विद्वान वकील का तर्क है, अपील खारिज की जाए।

17. पक्षों के विद्वान वकील को विस्तार से सुनने के बाद, हम अपीलकर्ताओं की दलील में बल पाते हैं। उत्तरदाताओं द्वारा दायर रिट याचिका में चुनौती अपीलकर्ताओं के महाप्रबंधक द्वारा जारी 8 दिसंबर 2004 के पत्र तक सीमित थी। उत्तरदाताओं ने दिनांक 5 जून 2004 के पत्र द्वारा 15 जुलाई 2004 तक अनुबंध अवधि के विस्तार को चुनौती नहीं दी थी। 30% अतिरिक्त काम आवंटित करने का अपीलकर्ताओं का निर्णय और जुर्माना लगाने का बोर्ड का निर्णय 27 अक्टूबर, 2005 को लिया गया और अनुमोदन आदेश दिनांक 3 नवंबर 2005 के माध्यम से उत्तरदाताओं को सूचित किया गया। हालाँकि, उच्च न्यायालय ने न केवल 8 दिसंबर 2004 के पत्र को बल्कि 3 नवंबर 2005 के अनुमोदन आदेश को भी रद्द कर दिया है।

18. ऐसा करने के लिए उच्च न्यायालय ने अनुबंध के खंड 5 का सहारा लिया है। उस खंड को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। अनुबंध के अन्य नियमों और शर्तों को समग्र रूप से पढ़ा जाना चाहिए। 26 मई 2003 के समझौते का खंड 5 अपीलकर्ताओं को अनुबंध के अस्तित्व में रहते हुए निविदा की गई मात्रा को +/- 30% तक कम करने या बढ़ाने का अधिकार देता है। निर्विवाद रूप से, मूल अनुबंध अवधि 15 अप्रैल, 2004

तक थी। इन उत्तरदाताओं के कहने पर, इसे 15 जुलाई 2004 तक बढ़ा दिया गया। विस्तारित अनुबंध अवधि यानी 15 जुलाई 2004 की समाप्ति से पहले, 11 जून 2004 को उत्तरदाताओं को अतिरिक्त 30% काम आवंटित किया गया था। चूंकि अनुबंध की अवधि बढ़ा दी गई थी और निर्णय को अंतिम रूप देने की अनुमति दी गई थी, इसने अनिवार्य रूप से उत्तरदाताओं को मूल समझौते के तहत सभी संविदात्मक शर्तों को पूरा करने के लिए बाध्य किया, जिसमें काम की निर्धारित मात्रा को पूरा करना भी शामिल था - चाहे वह मूल मात्रा हो या अतिरिक्त मात्रा - 15 जुलाई, 2004 से पहले। यह तथ्य कि कम अनुबंध दर के कारण उन्हें वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा, उस अनुबंध संबंधी दायित्व से मुक्त होने के बहाने के रूप में उद्धृत नहीं किया जा सकता है।

19. कार्य की मूल मात्रा या अतिरिक्त कार्य को निष्पादित करने की संविदात्मक बाध्यता का पालन करने में विफलता, जैसा भी मामला हो, अधूरे काम की सीमा तक अनुबंध के अन्य स्पष्ट खंडों के संदर्भ में अपीलकर्ताओं को मुआवजा देने के दायित्व के साथ उत्तरदाताओं का दौरा करना चाहिए और विशेष रूप से उसी कार्य को तीसरी एजेंसी के माध्यम से उच्च दर पर निष्पादित कराने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई वित्तीय हानि। तथ्य यह है कि उत्तरदाताओं ने 15 जुलाई 2004 से पहले 108.47% कार्य निष्पादित किया, उन्हें अधूरे अनुबंध कार्य (130% में से) के

लिए अपीलकर्ताओं को उचित राशि के साथ मुआवजा देने के दायित्व से मुक्त करने का कोई औचित्य नहीं हो सकता है।

20. संभवतः इस स्थिति से छुटकारा पाने के लिए, समझौते के खंड 5 पर भरोसा करने वाले उत्तरदाताओं का तर्क होगा कि अतिरिक्त मात्रा में काम उन्हें आवंटित नहीं किया जा सकता है, 45 स्पष्ट दिनों के नोटिस के अभाव में, वह भी अनुबंध अवधि के अंत में। यह तर्क, हमारी राय में, उक्त खंड का पूरी तरह से गलत अर्थ है। यह कहना एक बात है कि ठेकेदार को उसके द्वारा निष्पादित की जाने वाली अतिरिक्त मात्रा के अनुरूप अतिरिक्त कार्य पूरा करने के लिए पर्याप्त समय दिया जाना चाहिए। हालाँकि, कानून में, यह तर्क देना संभव नहीं है कि भले ही अनुबंध की अवधि अभी भी विद्यमान है, प्रिंसिपल (अपीलकर्ता) अनुबंध अवधि के भीतर ठेकेदार द्वारा निष्पादित किए जाने वाले उस खंड के तहत अनुमत सीमा तक काम की मात्रा बढ़ाने के अपने विकल्प का प्रयोग नहीं कर सकता था। प्रिंसिपल (अपीलकर्ताओं) को अनुबंध अवधि को 15 जुलाई, 2004 से आगे बढ़ाने के अपने विकल्प का उपयोग करने के लिए कहा जा सकता है, ताकि उत्तरदाताओं को अधूरे अतिरिक्त काम को पूरा करने में सक्षम बनाया जा सके। यदि ऐसा अनुरोध उत्तरदाताओं द्वारा किया जाना था, तो समझौते के खंड 5 के संदर्भ में काम की बढ़ी हुई मात्रा के अनुरूप संपर्क अवधि बढ़ाने के लिए अपीलकर्ताओं पर संबंधित दायित्व होता। इसके बजाय, उत्तरदाताओं ने केवल इस कारण से अनुबंध से बाहर निकलने का विकल्प चुना कि

उनके द्वारा सहमत अनुबंध दर बहुत कम थी और इससे उन्हें वित्तीय नुकसान हो रहा था। यह उनके संविदात्मक दायित्व को पूरा न करने का कोई उचित कारण नहीं हो सकता है।

21. खंड 5 में तीसरे वाक्य (अंतिम वाक्य) पर भरोसा करते हुए, यह तर्क दिया गया कि नियोक्ता 45 स्पष्ट दिनों के नोटिस के अभाव में निविदा की मात्रा में वृद्धि नहीं कर सकता था। हम अपीलकर्ताओं से सहमत हैं कि उक्त शर्त तभी लागू होगी जब उत्तरदाताओं को मशीन की क्षमता को 30% अतिरिक्त "दैनिक" मात्रा तक बढ़ाने के लिए भी कहा जाएगा। वर्तमान मामले में, अपीलकर्ताओं ने उत्तरदाताओं को दैनिक मात्रा बढ़ाने की आवश्यकता के बिना केवल 30% अतिरिक्त मात्रा आवंटित की। अनुबंध अवधि के दौरान अतिरिक्त मात्रा बढ़ाने और अतिरिक्त "दैनिक" मात्रा बढ़ाने के बीच स्पष्ट अंतर है। बाद के मामले में, ठेकेदार को मशीन की क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता होगी जिसके लिए उसे 45 स्पष्ट दिनों का नोटिस देना आवश्यक है। यह देखने के लिए पर्याप्त है कि खंड 5 के तीसरे वाक्य में 45 स्पष्ट दिनों के नोटिस का प्रावधान अपीलकर्ताओं के लिए 30% तक अतिरिक्त मात्रा में काम आवंटित करने में बाधा नहीं था, जबकि अनुबंध की अवधि विद्यमान थी।

22. उत्तरदाताओं ने तब परियोजना अधिकारी दिनांक 26 जनवरी 2005 की नोटिंग पर भरोसा करते हुए तर्क दिया था कि अनुबंध अवधि के अंत में उत्तरदाताओं को अतिरिक्त काम सौंपने पर उक्त अधिकारी द्वारा भी

संदेह किया गया था। परियोजना अधिकारी की टिप्पणियाँ अनुबंध के खंड 5 के दायरे को समझने का आधार नहीं हो सकती हैं। इसके अलावा, यह केवल एक अंतर-विभागीय संचार था जिस पर अपीलकर्ताओं के कार्यालय में विभिन्न स्तरों पर विधिवत विचार किया गया था, लेकिन अंततः अपीलकर्ताओं के निदेशक मंडल का निर्णय ही मान्य होना चाहिए। वास्तव में, समझौते का खंड 5 अपीलकर्ताओं को अनुबंध के अस्तित्व में रहने के दौरान अनुमेय सीमा तक काम की मात्रा बढ़ाने या घटाने का अधिकार देता है। उस शक्ति का प्रयोग करने के बाद, अनुबंध अवधि या विस्तारित अनुबंध अवधि के भीतर विषय अनुबंध के संदर्भ में अतिरिक्त कार्य को पूरा करने के लिए ठेकेदार का दायित्व अनिवार्य था। उत्तरदाताओं का यह तर्क सही नहीं है कि अपीलकर्ता-कंपनी के पास बढ़ी हुई मात्रा को पूरा करने के लिए समय विस्तार देने का कोई अधिकार नहीं था। अन्य अनुबंध शर्तों जैसे खंड 11.0 - निर्धारित मात्रा, सीमा और दर में भिन्नता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए, यह तर्क अस्वीकार किए जाने योग्य है; खंड 13 - अनुबंध पूरा करने का समय और विशेष रूप से खंड 14.0 - पूरा होने की तारीख के विस्तार के लिए। खंड 14.0 (ई) उपलब्ध था और इस स्थिति में उत्तरदाताओं द्वारा इसे लागू किया जाना चाहिए था। इसमें कहा गया है कि किसी अन्य कारण से जो विशेष रूप से उसी खंड के उप-खंड (ए) से (डी) में प्रदान नहीं किया गया है, अपीलकर्ताओं के विवेक पर, पूरा होने की तारीख बढ़ाई जा सकती है, यदि ठेकेदार के नियंत्रण से बाहर की स्थिति के कारण यह आवश्यक पाया गया। उस खंड को उस स्थिति के लिए लागू

किया जा सकता है जिसमें उत्तरदाताओं को अनुबंध (विस्तारित) अवधि के अंत में उन्हें आवंटित अतिरिक्त कार्य के कारण रखा गया था।

23. हमारी राय में, खंड 5 ने प्रिंसिपल (अपीलकर्ताओं) को मौजूदा अनुबंध अवधि के 45 स्पष्ट दिनों की कमी के कारण अतिरिक्त 30% मात्रा तक काम आवंटित करने पर रोक नहीं लगाई है। जबकि, उस विकल्प का प्रयोग अपीलकर्ता किसी भी समय अनुबंध अवधि के अस्तित्व में रहने तक कर सकते थे, जो इस मामले में 15 जुलाई 2004 तक था। वर्तमान मामले में, समझौते के खंड 5 के तहत अनुमेय 30% तक काम में वृद्धि के संबंध में ऐसा नोटिस 11 जून 2004 को दिया गया था। इस निष्कर्ष पर, यह मानना चाहिए कि उत्तरदाताओं ने 130% कार्य (अर्थात् 130 - 108.47%) में से शेष कार्य पूरा न करके, अपने संविदात्मक दायित्व का उल्लंघन किया है। उस हद तक प्रतिवादी अपीलकर्ताओं को क्षतिपूर्ति देने के लिए उत्तरदायी हो गए, जिसमें जुर्माना भी शामिल है और विशेष रूप से अधूरे काम को किसी तीसरी एजेंसी (ठेकेदार) को उच्च दर पर सौंपने के कारण अपीलकर्ताओं को हुई वित्तीय हानि की भरपाई करना शामिल है। अपीलकर्ताओं द्वारा मांगी गई राशि में संविदा दर का अंतर और तीसरी एजेंसी (ठेकेदार) के माध्यम से उच्च दर पर अधूरे काम को पूरा करने के लिए अपीलकर्ताओं को हुई वास्तविक हानि शामिल है, जैसा कि उत्तरदाताओं को दिनांक 8 दिसंबर, 2004 को भेजे गए संचार से पता चला है।

24. उत्तरदाताओं ने तब तर्क दिया कि, अपीलकर्ताओं ने प्रतिवादियों को कोई अवसर दिए बिना एकतरफा जुर्माना लगाया और महाप्रबंधक की नोटिंग के बावजूद कि अपीलकर्ताओं को उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ। इसी प्रकार, परियोजना अधिकारी द्वारा उत्तरदाताओं को अनुबंध अवधि के अंत में अतिरिक्त कार्य दिए जाने के संबंध में संदेह व्यक्त किया गया था। उत्तरदाताओं ने मौला बक्स बनाम भारत संघ में इस न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया है, जिसमें यह माना गया है कि "जहां अनुबंध में जुर्माने की प्रकृति में एक राशि का नाम दिया गया है, जहां धन के संदर्भ में नुकसान का निर्धारण किया जा सकता है, मुआवजे का दावा करने वाली पार्टी को अपने द्वारा हुए नुकसान को साबित करना होगा।" हालाँकि, यह निर्विवाद है कि अधूरे काम को तीसरी एजेंसी (ठेकेदार) को उच्च दर पर सौंपने के कारण अपीलकर्ताओं को वित्तीय नुकसान उठाना पड़ा। उसमें उत्तरदाताओं द्वारा किये जाने वाले समान कार्य की अनुबंध दर 17/- रुपये प्रति घन मीटर होती, जिसे अपीलकर्ताओं को तीसरी एजेंसी के माध्यम से 31.50 रुपये प्रति घन मीटर की दर से निष्पादित करना था। यह तथ्य कि अपीलकर्ताओं को उत्पादन का कोई नुकसान नहीं हुआ, उत्तरदाताओं को उस दायित्व से मुक्त नहीं किया जा सकता। यह अलग बात है कि जुर्माने के साथ वित्तीय हानि की वसूली के लिए अपीलकर्ताओं द्वारा अंतिम निर्णय लेने से पहले उत्तरदाताओं को सूचित नहीं किया गया था। उत्तरदाता अनुबंध के खंड 30.3 के संदर्भ में दंड की अपनी मांग पर पुनर्विचार के लिए अपीलकर्ताओं से संपर्क कर सकते थे; और अपीलकर्ताओं को उनसे वसूल

की जाने वाली जुर्माना राशि माफ करने के लिए राजी करें। हालाँकि, उत्तरदाताओं ने रिट याचिका के माध्यम से सीधे उच्च न्यायालय का रुख करने का विकल्प चुना। विशेष रूप से, उच्च न्यायालय ने जुर्माने की राशि को रद्द नहीं किया है, लेकिन पूरी मांग अस्वीकार्य है। चूंकि हमने उच्च न्यायालय के निष्कर्षों और निष्कर्षों को उलट दिया है और भले ही यह अपील सफल हो जाती है, उत्तरदाताओं को अपीलकर्ता कंपनी - कंपनी को प्रतिनिधित्व करने का अवसर दिया जा सकता है, जो बदले में कानून के अनुसार इससे निपट सकती है। . यदि अपीलकर्ता दंड या उसकी मात्रा के अन्याय के बारे में उत्तरदाताओं के दावे को स्वीकार करते हैं, तो वे सलाह दिए जाने पर दंड राशि की वसूली के लिए अपने दावे को वापस लेने या संशोधित करने के लिए स्वतंत्र होंगे। ऐसी स्थिति में, अपीलकर्ता प्रतिनिधित्व को अस्वीकार कर देते हैं, वे जुर्माने के रूप में मांग की गई राशि और उस पर अर्जित ब्याज की वसूली करने के लिए स्वतंत्र होंगे, जैसा कि कानून में अनुमति हो सकती है। हालाँकि, यह उत्तरदाताओं को अनुबंध की दर और अपीलकर्ताओं द्वारा अनुबंध मात्रा के 130% में से अधूरे काम को पूरा करने के लिए तीसरी एजेंसी के माध्यम से उच्च दर पर किए गए वास्तविक लागत के अंतर के कारण उत्पन्न होने वाली वित्तीय देनदारी से मुक्त नहीं करेगा। इसे अपीलकर्ताओं द्वारा उत्तरदाताओं से उस पर अर्जित ब्याज के साथ उस दर पर वसूल किया जा सकता है, जो कानून में स्वीकार्य हो, भले ही जुर्माना राशि को वापस लेने या संशोधित करने के लिए उत्तरदाताओं द्वारा किया गया प्रतिनिधित्व विचाराधीन हो। उपरोक्त को

ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए इस निर्णय पर उत्तरदाताओं के इस तर्क का बोझ डालना आवश्यक नहीं है कि उत्तरदाताओं को बिना किसी नोटिस या सुनवाई के लगाया गया जुर्माना निष्प्रभावी है; साथ ही गोरकला सिव्योरिटी सर्विसेज बनाम गवर्नमेंट (एनसीटी ऑफ दिल्ली) और अन्य 1 और कुंवारी स्लिरिलेकलिया विद्यार्थी और अन्य बनाम यूपी राज्य के मामले में भी निर्णय उस विवाद के समर्थन में थे।

25. इसी तरह, हमारे लिए इस निर्णय पर उत्तरदाताओं द्वारा भरोसा किए गए निर्णयों का बोझ डालना आवश्यक नहीं है, यह तर्क देने के लिए कि वैकल्पिक उपचार का अस्तित्व भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट याचिका पर विचार करने में कोई बाधा नहीं है, जैसा कि पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट बनाम सिटी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, हरबंसलाल सल्लिया और अन्य बनाम इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य-', यूनियन ऑफ इंडिया और अन्य बनाम टांटिया कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, एम.पी.स्टेट एग्रो के मामलों में माना गया है। उद्योग विकास निगम एवं अन्य. बनाम जाल्वन क्लान और व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेड मार्क्स रजिस्ट्रार, मुंबई। क्योंकि, हमने पहले ही विवाद के गुणों की जांच कर ली है और प्रतिवादियों को जुर्माने या उसकी मात्रा की मांग के औचित्य के सवाल पर अपीलकर्ताओं को प्रतिनिधित्व करने की स्वतंत्रता दी है। यह उत्तरदाताओं के लिए उस संबंध में उपाय करने के लिए खुला होगा, जैसा कि कानून में अनुमत हो सकता है। हम जुर्माने की राशि के मुद्दे पर किसी

तरह की कोई राय व्यक्त नहीं कर रहे हैं. इस संबंध में सभी प्रश्न खुले छोड़ दिए गए हैं।

26. तदनुसार, हम आंशिक रूप से इस अपील को स्वीकार करते हैं। डिवीजन बेंच के 7 नवंबर 2012 के फैसले को रद्द कर दिया गया है। रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा दावा की गई राहत का निपटान उपरोक्त शर्तों के अनुसार किया जाता है।

27. उपरोक्त शर्तों में लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।

कल्पना के.त्रिपाठी

अपील आंशिक रूप से स्वीकार की गई।

(यह अनुवाद एआई टूल: SUVAS की सहायता से अनुवादक रुचिका गुलेच्छा द्वारा किया गया है)

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।